RAJYA SABHA

Friday, the 24th November, 2006/3 *Agrahayana,* 1928 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*41. [The questioner (Shri Shatrunghan Sinha) was absent. For answer *vide* page *34 infra.]*

स्टेशनों पर कृषि उत्पाद विपणन केंद्र

*42. **सुश्री अनुसुइया उइके** : **क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पाद विपणन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं व सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों से किसानों को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलू): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) परिवहन के एकीकरण द्वारा कृषि उत्पाद संग्रहण एंव उसकी दुकानों को प्रोत्साहन देने की नीति पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है, उपर्युक्त के लिए एक नीतिगत ढांचे का अवधारणात्मक दस्तावेज तैयार करने के लिए कार्यपालक निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) इस नीति से किसानों और सामान्य अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इस संबंध में ब्यौरा किया जा रहा है।

Agricultural products' outlets at stations

†*42. MISS ANUSUIYA UIKEY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether agricultural products' outlets are being set up at railway statiops;

(b) if so, the details of services and facilities that would be made available at these outlets;

(c) Whether farmers would be benefited by these outlets; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R VELU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statemont

(a) and (b) A policy to promote Agriculture Products collection and distribution outlets with integration of transportation is under active consideration. A committee of Executive Directors has been formed to prepare a concept paper for above policy frame work.

(c) and (d) Farmers and the economy in general will be benefited by this policy. The details are being worked out.

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने "क" और "ख" के उत्तर में बताया है कि "परिवहन के एकीकरण द्वारा कृषि उत्पाद संग्रहण एंव उसकी वितरण दुकानों को प्रोत्साहन देने की नीति पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त के लिए एक नीतिगत ढांचे का अवधारणात्मक दस्तावेज तैयार करने के लिए कार्यपालक निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है"। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ये केन्द्र कब तक प्रारम्भ किए जाएंगे? साथ ही देश भर में कितने स्टेशनों पर ऎसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि समिति की रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है, तब तक के लिए तात्कालिक व्यवस्था क्या की जा रही है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं?

SHRI R. VELU: Sir, during the last Monsoon Session, the hon. Minister for Railways, Shri Lalu Prasad, made a policy announcement saying that

† Original notice of the question was received in Hindi.

after independence, there has been no proper arrangement for collection, storage, transportation and distribution of agricultural commodities, mainly, fruits, vegetables, milk and foodgrains. The farmer does not get the proper price for it. At the same time, the consumer also does not get it at reasonable price and only the intermediaries stand to benefit.

Sir, as the hon. Member wanted to know, we have got a network of near about 8,000 stations in our country, even if you take 80 per cent of them it comes to 6,400 stations, and, on, what you call, the hub-and-spokes model, we thought it fit that to make every station a spoke and create hub in a town or a city like that so that these products are collected from the villages, distributed either through the outlets at the stations or transported to the areas where these are required. Sir, as you know very well, that we have been transporting hitherto the foodgrains to various places. As far as potatoes, onions, mangoes etc. are concerned, we have done it but not these agricultural products, which are perishable and which are produced in various villages. First point is that about 8,000 stations or its 80 or 60 per cent stations will be used as outlets. With regard to the second thing that the hon. Member wanted to know, we have now constituted a committee, comprising four directors, which is going into the details of it; how to go about it. They are given a month's time to frame the policy as such, modalities as such, so that we can implement the same. Mainly, we are now making a public-private partnership. We are having a dialogue with many corporates and interested parties saying that they can join us. There are two things to do in Railways. One thing is, we have got spareabie surplus land which can be used for constructing warehouses and outlets. We can also use it for transportation. ...*(Interruptions)*... I am only saying what it is because she wajited to know... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You please stick to the reply.

SHRI R. VELU: So, we have said that a month's time is given to do it.

सुश्री अनुसुइया उइके : माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के "ग" और "घ" जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर में "इस नीति से किसानों और सामान्य अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है" –ऐसा माननीय मंत्री जी ने बताया है। इसमें मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि यह ब्यौर कब तक तैयार होकर कार्यरुप में परिणत होगा?

SHRI R. VELU: Now, it is in nascent stage. I have told that we are now having a dialogue with various corporates. We will have, at least, one ' or two months' time to evolve a policy as such.

श्री दत्ता मेघे : सर, यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे कृषि मंत्रालय से इस संबंध में चर्चा करके अच्छी स्कीम लाएं, ताकि किसानों को और लोगों को उससे फायदा हो। कृषि मंत्रालय से बात किए बगैर अच्छी स्कीम कैसे आएगी ? यह पब्लिसिटी स्टंट न हो, यह एक अच्छी स्कीम है और अगर कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिलकर कुछ करेंगे, तो कुछ फायदा होगा।

श्री सभापति : आप कृषि मंत्री जी से बात कर लीजिए, यहीं बैठे हैं। श्री प्यारे लाल खंडेलवाल पूछिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सभापति जी, मेरा प्रश्न आ गया है।

श्री सभापति : आ गया है, तो ठीक है। डा. मलयसामी, पूछिए।

DR. K. MALAISAMY: Thank you Sir. Though it is very much belated, it is a very good move. I would like to ask the hon. Minister whether before finalisation of all his concept or initiative or policy etc., as seen now, it has bee only conceived, before delivery, he can concult the farmers' forum as to what they really need and whether their requirements can be met.

SHRI R. VELU: Though the suggestion by the hon. Member is well taken, I am thankful to the hon. Member, not only this farmers' forum, but we are also going to consult industries, commerce and other kinds of forums available to us.

दिल्ली में प्रदूषण

*43. **डा. मुरली मनोहर जोशी**:†
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक स्थानों पर प्रदूषण होने के कारण यहां का वातावरण मानव जीवन के प्रतिकूल बन चुका है;

(ख) यदि हां, तो आई.टी.ओ. व चांदनी चौक इलाकों के अतिरिक्त वे अन्य इलाके कौन-कौन से हैं जहां का वातावरण प्रदूषित हो जाने के कारण मानव-जीवन के प्रतिकूल हो चुका है; और

† सभा में यह प्रश्न डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।